must give utmost importance to the development and reorientation of primary level education in the country.

Demand to take measures to check the disposal of industrial effluents and wastes in the rivers to protect them from pollution

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश): सर, आदि काल से नदियाँ मानव के लिए जीवनदायिनी रही हैं। उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है और उन्हें यथासंभव शुद्ध रखने की मान्यता व परंपरा है। आज देश की 70 फीसदी नदियाँ प्रदूषित हैं और मरने के कगार पर हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अध्ययन में कहा है कि देश-भर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों का 70 फीसदी गंदा पानी पेयजल की प्रमुख स्रोत नदियों में बिना शोधन के ही छोड़ दिया जाता है। वर्ष 2008 तक के उपलब्ध आँकड़ों के मुताबिक ये शहर और कस्बे 38,254 एम.एल.डी. गंदा पानी छोड़ते हैं, जबकि ऐसे पानी के शोधन की क्षमता आज 11,787 एम.एल.डी. ही है। गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली और हिंडन, आंध्र की मुंसी, दिल्ली की युमना तथा महाराष्ट्र की भीमा नदियाँ सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। पिछले 40-50 वर्षों में अनियंत्रित विकास और औद्योगीकरण इसका प्रमुख कारण है। इनके पानी से लोग त्वचा रोग, पित्ताशय के कैंसर और आंत्रशोथ जैसी भयंकर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। दिल्ली के 56 फीसदी लोगों की जीवनदायिनी, उनकी प्यास बुझाने वाली, यमुना आज खुद अपने ही जीवन के लिए जूझ रही है। देश् की प्रदूषित हो चुकी नदियों को साफ करने का अभियान पिछले लगभग 20 वर्षों से चल रहा है। इस काम में अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, किन्तु परिणाम शून्य है।

अतः सरकार इन नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु उद्योगों को प्रदूषित जल व कचरा नदियों में बहाने से रोकने हेतु ठोस कदम उठाए।

Demand to take action for the construction of an additional bridge over the river Narmada near Jadeshwar on NH-8 in Gujarat

श्री भरतसिंह प्रभातसिंह परमार (गुजरात): उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग-8 स्थित जडेश्वर के निकट नर्मदा नदी पर एक अतिरिक्त पुल के निर्माण की दिशा में क्या स्थिति का कोई अवलोकन किया गया है?

महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रदेश की सरकार को यह सूचित किया गया है कि इस नर्मदा नदी पर नए पुल का निर्माण B.O.T. द्वारा ही किया जाना है और कंसेशन समय सीमा पूर्ण होने के उपरांत ही यानी दिसंबर, 2012 के बाद ही नए पुल का निर्माण किया जा सकेगा। प्रतिदिन सौराष्ट्र-कच्छ से मुंबई तक के यातायात का आवागमन इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है और देश का अधिकांश वाणिज्य अर्जन भी गुजरात और मुंबई के बीच इसी राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है।

प्रतिदिन लाखों की संख्या में यातायात का आवागमन होने के कारण जडेश्वर स्थित इस पूल पर यातायात के निकास की समस्या एक सिरदर्द साबित हो रही है और बड़ोदरा-सूरत के बीच छह मार्गीय राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का उद्देश्य सार्थक साबित नहीं हो रहा है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से इस सदन के माध्यम से अनुरोध है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा जडेश्वर के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर वर्ष 2010-11 के दौरान नए पुल का निर्माण कराने की दिशा में तत्काल उचित कदम उठाने के निर्देश जारी करें। प्रदेश ने अपने राजपत्र दिनांक 07.09.2009 के द्वारा आपके मंत्रालय से इस स्थिति को निपटाने के लिए विशेष आग्रह किया है और इसके लिए तत्काल कोई विशेष कदम उठाने का अनुरोध किया है।

अंत में मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं इस पुल के निर्माण के संबंध में हस्तक्षेप करें, जो कि राष्ट्र के हित में है।